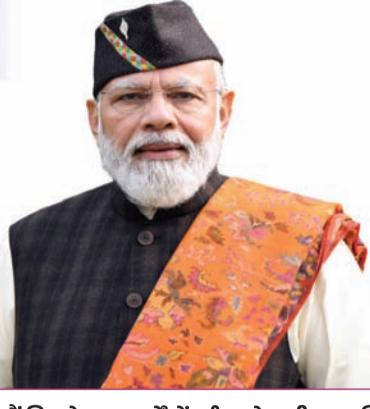


डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड

प्रगति की ओर अग्रसर



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखण्ड विशेषकर बद्धीनाथ और केदारनाथ के साथ गहरा संबंध है और उनकी यात्राओं
और इन प्रमुख तीर्थ स्थलों के विकासकार्यों के लिए किए गए दूरदर्शी प्रयासों में साफ देखा जा सकता है



बद्धीनाथ और केदारनाथ से मिल रहा आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा

“मानवीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शित में हम अपने राज्य के सभी विकास, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विवास और अपार संभावनाओं को निखारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य की प्रगतिशील नीतियों और उत्तराखण्ड के पहले के माध्यम से हम आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर की दिशा में अग्रसर हैं। हमारा लक्ष्य उत्तराखण्ड को प्रगतिका एक मॉडल बनाना है जहाँ परंपरा और नवीनता का संगम होता है और जहाँ हर व्यक्ति गाज़ की समृद्धि और कल्पना के लिए कार्य कर विकास में योगदान देता है।

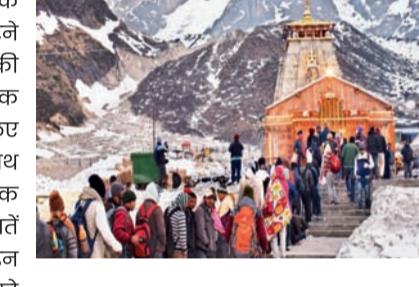
पृष्ठक सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड



अपनी प्राकृतिक सौन्दर्यता के लिए भी विश्व स्तर पर श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों का आकर्षित करता है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को बीच स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिलिंगों में से एक के ढप में प्रसिद्ध है। यह प्रतिष्ठित चारथाम यात्रा का अहम पड़ाव ही है। यहाँ के आध्यात्मिक महत्व को बनाए रखने के साथ जुड़े पुनर्जीवन उपायों ने केदारनाथ को उत्तराखण्ड का पुराना गौरव पाने में मदद की है, जिससे दुनिया भर से तीर्थयात्री आकर्षित होकर यहाँ आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल ही में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के उद्घाटन से केदारनाथ में नए विकास पर बल दिया जा रहा है। आदि गुरु शंकरचार्य की प्रतिमा के अनावरण से लेकर सरदरती दर्शनी वाले और केदारनाथ के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें आदि गुरु शंकरचार्य की प्रतिमा के निमिण से लेकर प्रगति का प्रत्यक्ष अवलोकन करने तक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रणनीति केदारनाथ की पवित्रता बनाए रखने के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है।

उत्तराखण्ड के आध्यात्मिक महत्व को बनाए रखने के साथ केदारनाथ में पुनर्जीवन कार्योंने उसके पूर्ण गौरव को बढ़ा दिया है, जो दुनिया भर से तीर्थ यात्रियों को दान्य की ओर आकर्षित कर रहा है।



दिया है, बल्कि अंतराखण्डीय स्तर पर इसकी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया है। बद्धीनाथ और केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अटूट आस्था ने उत्तराखण्ड के पुनर्जीवन के प्रस्तुति किया है। द्रुदर्शी प्रयासों और नए विकास कार्यों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन धार्मिक स्थानों को पुनर्जीवित कर समर्पित कर रहा है।

करती है। इन प्रयासों के चलते उत्तराखण्ड में आध्यात्मिक पर्यटन और तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार उछिले देखी जा रही है। ऑल वेटर रोड परियोजना, जिसे चारथाम साइक एक्सप्रेस अवलोकन के रूप में भी जाना जाता है, यह उत्तराखण्ड के चार धार्मों को जोड़कर भक्तों और आंतर्मंत्री के लिए विश्वासी धार्मों को संभव बनाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इसी तरह से ऋषिकेश-कपरियाग रेल परियोजना, अपनी उद्यानीलता और साइरल तकनीकी के साथ केदारनाथ और आम-पास के क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार करने के लिए संकरित है। केदारनाथ के पुनर्जीवन को दर्शाती है। केदारनाथ की धार्मिक स्थानों के उपयोग के प्रति उनके समर्पण ने नेतृत्व किया है।



धार्मिक वैभव को पुनर्जीवित करता मानसखंड मंदिर माला मिशन

‘मानसखंड मंदिर माला मिशन’ के हृदय स्थल के रूप में यहाँ के 48 पौराणिक मंदिरों को पुनर्जीवित और पुनर्जीवित किया जा रहा है।

इसमें कुमाऊं के विभिन्न जिलों में फैले 16 पौराणिक मंदिरों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

उत्तराखण्ड कई प्राचीन मंदिरों और पवित्र स्थलों की भूमि है। धार्मी ने इन मंदिरों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व यही कारण है कि यह देवभूमि के रूप में विश्विलेख है। ये को समझते हैं और मंदिरों के वारुदीलिपि चमत्कारों को मंदिर कुमाऊं क्षेत्र में फैले हुए हैं और लंबे समय से आस्था पुनर्जीवित और पुनर्जीवित करने के लिए आनंद देते हैं। यहाँ भारत मिशन के तहत एक दूरदर्शी पहल शुरू की है। इस दूनिया के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं का आना लगा रहा प्रयास का मूल 48 पौराणिक मंदिरों को पुनर्जीवित और उत्तराखण्ड की वादियों में द्वितीय ऐसे मंदिरों तक भक्तों के पुनर्जीवित और श्रद्धालुओं की पहुंच बनाने को लेकर धार्मी सरकार विशेष रूप से फैले 16 मंदिरों पर विशेष जोर दिया गया है। सैकड़ों वर्षों से प्रयास कर रही है। प्रदेश के ऐसे कई धार्मिक स्थलों, जिनके आस्था का केंद्र देवताओं के देवताओं की विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया गया है। उत्तराखण्ड के मरुधर्मीनंत्री पुष्कर सिंह धार्मी का विजयन के रूप में भी जाना जाना चाहता है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक स्थलों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है।

उत्तराखण्ड के विवाह की दिशा में विशेष जोर दिया जाता है। उत्तराखण्ड के स

उत्तर प्रदेश : कानून व्यवस्था के दावे और हकीकत

पिछले दिनों कबीर नगर में खलीलाबाद के डीघा गांव में अज्ञात लोगों द्वारा उनके साथ उन्हीं के घर में घुस कर कथित तौर पर पहले सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में उनके शरीर को चाकुओं के गार से छन्नी कर दिया गया। जिसके चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गयी और हत्यारे घटना को अंजाम देकर फरार हो गये। नदिनी राजमहर का लहूलुहान शव उनके कमरे में फर्श पर पड़ा मिला। क्या इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले को इस बात का जरा भी भय नहीं था कि हँड़अगले चौराहे पर उनका इंतजार यमराज का रहे होंगे?



नमल रान लेखिका

नहीं बाल्कि राजनातिक दृष्टि से भा वय सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यह राज्य के बीच हाई प्रौफाइल राजनीतिज्ञों सहित्यकारों, कवियों, शायरों का हाँ नहीं बल्कि हाई प्रौफाइल अपराध व अपराधियों का भी गढ़ है। यहाँ वें बेखौफ अपराधियों के लिये कर्भ भी और किसी भी जगह बड़े से बड़े अपराध को अंजाम देना मामूली बात है। फिर चाहेकोई व्यक्ति था जो ऐसे में हो, पुलिस कस्टडी में या जेल में या भीड़ भाड़ के इलाके में या अपराध को सुरक्षित समझते हुये अपने घर में चैन से सो रहा हो, किसी भी जगह हत्या को अंजाम देना ऐसे शातिक अपराधियों के लिये मामूली बात है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का विषय अक्सर चुनावी मुद्दा भी बनता रहता है। प्रत्येक राजनीतिक दल एक दूसरे पर कानून व्यवस्था के मामले में असफल होने और अपराध का बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहते हैं राज्य की वर्तमान सरकार तो प्रदेश कर्म कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का कुछ ज्यादा ही दिंदोरा पीटती रहती है

अपराधमुक्त बनान का जहा दावा करते रहते हैं वहीं वह यह बताने से भी नहीं चूकते कि पिछली (सपा) सरकार में माफिया व अपराधी बेखौफ घूमा करते थे। 17 सितम्बर 2023 को उनके गृह नगर गोरखपुर में दिया गया योगी के भाषण का यह अंश कानून व्यवस्था के प्रति उनके नजरिये को दर्शाता है या यह सिर्फ तालियां पिटवाने के लिये की गयी लफ़फ़ाज़ी थी, यह तो राज्य की आपराधिक घटनाएं ही बता रही हैं। उस समय मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि -हक्कानून सरक्षण के लिए है। लेकिन कानून को बंधक बनाकर व्यवस्था में संघ लगाने का प्रयास करने की इजाजत किसी को नहीं है। कानून सुरक्षा के लिए है, लेकिन यदि किसी ने बहन-बेटी के साथ छेद्याना की तो अगले चौराहे पर उस शोहदे का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमें सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण देना होगा। तो क्या मुख्यमंत्री की इस चेतावनी के बाद राज्य की कानून व्यवस्था अपराधा म काह कमा आइ या पक्का यह भी महज ह्यफिल्मी डायलॉगों का या फिर जुमला साबित हुआ? राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था स्वयं इस बात का सूबूत है। आम महिलाओं के साथ होन वाली बलात्कार व शारीरिक शोषण की अनेक घटनाओं की तो बात ही छोड़िये इस राज्य में तो अब हाई प्रोफाइल महिला नेता भी सुरक्षित नहीं रहीं। यहां तक कि सत्र से जुड़े लोगों को भी अपराधी बेखौफ अपना निशाना बना रहे हैं। ताजातरीय उदाहरण उत्तर प्रदेश में भाजपा वेस्ट सहयोगी दल सुहैलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) की वरिष्ठ महिला नेत्री नंदिनी राजभर की हत्या का है नंदिनी राजभर सुभासपा की महिला विंग की प्रदेश महासचिव थीं। पिछले दिनों कबीर नगर में खलीलाबाद वेस्ट डीगा गांव में अज्ञात लोगों द्वारा उनके साथ उन्हीं के घर में घुस कर कथित तौर पर पहले सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में उनके शरीर को चाकुओं के बार से छन्नी के दिया गया। जिसके चलते मौके पर ह

2019 का उत्तर प्रदेश का सानभद्र जिले के घोरावल थाना क्षेत्र के उम्भा गांव में हुआ था जबकि लगभग 30 ट्रैक्टर में भरकर आए 150 सशस्त्र लोगों ने जिनके पास कथित तौर पर 10 से अधिक राइफलें थीं। जब इन सशस्त्र हमलावरों को रोकने के लिए गांव वालों ने गुहार लगाई तो उन्होंने उन पर ही गोलियों बरसानी शुरू कर दीं। नवीजतन 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी। योगी सरकार के प्रदेश में चाक चौबंद कानान व्यवस्था के दावों के बीच अपराधियों द्वारा ऐसी अनेक आपराधिक घटनायें प्रदेश में आये दिन अंजाम दी जाती हैं। महिलाओं के साथ भी आये दिन अपराध होते रहते हैं। परन्तु इन वास्तविताओं को नजरअंदाज कर इहें उत्तर प्रदेश या मणिपुर जैसी डबल इंजन की सरकारों वाले राज्य की नहीं बल्कि केवल बंगाल और केरल की अपराधिक घटनायें ही नजर आती हैं। गोड़ा इहें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के अपने ही दावों और उसकी हकीकत में कोई फर्क नजर नहीं आता।

चल कर जात गणना आर आरक्षण बढ़ान क मुद्र का समर्थन करना पड़ रहा ह। बाका राज्य में भाजपा ने जाति गणना और आरक्षण के मुद्रों को हाशिए में डाला है। हिंदूत्व के एजेंट से दूर दिखाने वाली पार्टीयां और नेता भी भाजपा के हिंदूत्व व राष्ट्रवाद के एजेंट को स्वीकार करवे गठबंधन में शामिल हुए हैं। यहां तक कि किसानों के मुद्रे पर भी जयंत चौधरी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसानों के खिलाफ बही खड़ हो गए हैं। हैरानी नहीं होगी अगर इस मुद्रे के बावजूद अकाली दल का भी भाजपा से तालमेल हो। सवाल है कि प्रादेशिक पार्टीयां क्या अपनी राजनीतिक और वैयारिक जमीन छोड़ कर या उसके साथ समझौता करके भाजपा के साथ गठबंधन कर रही हैं? यह मामूली सवाल नहीं है। इसका सरल जवाब तो यह है कि सत्ता की दिवानगी में पार्टीयां हर तरह के समझौते कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति, धर्म और व्यापक रूप से सामाजिक व्यवस्था की अंतरिक्षिया का समझाने की भी जरूरत है।



लेखक

उसकी शर्तों पर हो रहा है, जबविं कांग्रेस सहयोगी पार्टियों की शर्तों पर गठबंधन कर रही है। यह दोनों पार्टियों की राजनीतिक स्थिति का फर्क भी बताता है। एक तरफ 10 साल से सत्त में रह कर बेहिसाब शक्ति और संपद इकट्ठा करने वाली भाजपा है तो दूसरी ओर राजनीति के बियाबान में भटवर रही कांग्रेस है, जो 10 साल से सत्त से बाहर है, राज्यों में कई जगह जीताई हुई सरकारें गंवा चुकी हैं और ज्यादाता नेता केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं तभी ऐसा लग रहा है कि वह कहीं भी गठबंधन करने के लिए अपनी शर्तें आरोपित करने की स्थिति में नहीं है। पिछले साल के अंत में हुए राज्यों के चुनाव में खराब प्रदर्शन ने कांग्रेस की मौलभाव करने की क्षमता को और कम कर दिया। अब स्थिति यह है कि वह महाराष्ट्र में दूसरे नंबर

धोषणा के बावजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिलकार्जुन खडगे कह रहे हैं कि अब भी तालमेल हो सकता है। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल में कई जगह समझौता करना पड़ा है। उसके नेता मजबूरी बताते हुए कह रहे हैं कि कैसे गुजरात में भरूच की अहमद पटेल की सीट आप के लिए छोड़ी पड़ी। लोकसभा सीटों के समझौते के नाम पर झारखण्ड में जेएमएम ने राज्यसभा की कांग्रेस की सीट हथिया ली है बहरहाल, कांग्रेस की कमजोरियां अपनी जगह हैं और सत्ता से बाहर होने के अलावा भी उसके कई कारण हैं। उसके बरबर भाजपा सभी नए और पुराने सहयोगी दलों के साथ अपनी शर्तों पर समझौता कर रही है। भाजपा ने 38 पार्टीयों का गठबंधन बनाया है लेकिन यह सुनिश्चित किया है कि पिछले एनडीए अपवाद है, जहां भाजपा को करनी पड़ रही है। लेकिन भी ऐतिहासिक कारण हैं। भाजपा कभी भी मजबूत तरही है। तभी उसे हमेशा नीतीश के सहारे की जरूरत पड़ती है। 2014 में अकेले लड़की भी उसे रामविलास पासवान उपेंद्र कुशवाहा के सहारे करके थी। 2019 से पहले भाजपा करके नीतीश की एनडीए में कराई थी और जब वे 2024 साथ छोड़ कर चले गए थे तभी नाराजगी के बावजूद 2024 उनकी वापसी कराई गई है। इस बार मामला थोड़ा उल्लंघन है। भाजपा पुराने सहयोगियों साथ में रखना चाहती है तभी उसकी संख्या का पेंच उलझ गया है अपने हिस्से की सीटें नहीं

सो, देश के बाकी राज्यों के मुकाबले भाजपा के लिए बिहार थोड़ा मुश्किल दिख रहा है फिर भी भाजपा सारे विवाद सुलझाने में जुटी है इसके मुकाबले देश के लगभग सभी राज्यों में भाजपा अपने हिसाब से समझौता कर रही है। यहां तक कि ओडिशा जैसे राज्य में, उसने सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को इस बात के लिए तैयार किया है कि वह भाजपा के लिए अपनी जीती हुई लोकसभा सीटें छोड़े। यह आमतौर पर नहीं होता है। ध्यान रहे भाजपा का पूरा फोकस इस समय लोकसभा चुनाव पर है। वह विधानसभा चुनाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है उस केंद्र में तीसरी बार सरकार बनानी है। प्रधानमंत्री ने दो मोदी ने इस बार भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए चार सौ सीटों का लक्ष्य रखा है। पिछली बार ओडिशा में भाजपा को छपर फाड़ सीटें मिली जनता दल की एनडीए में वापसी करा रही है और उसको इस बात के लिए तैयार किया है कि वह अपनी जीती हुई पांच सीटें छोड़े ताकि भाजपा 14 सीटों पर लड़े। बीजद की पांच जीती हुई सीटें लेने के बावजूद भाजपा उसे लोकसभा में एकतरफा बढ़त नहीं देना चाहती है। तभी वह 15 साल पुराने फॉम्यूले के आधार पर विधानसभा सीटों का बंटवारा चाहती है छह साल बाद टीटीपी की भी एनडीए में वापसी हो रही है और उसके साथ गठबंधन में भाजपा आंश्व प्रदेश की छह लोकसभा सीटों पर लड़ेगी। सोचें, पिछले चुनाव में भाजपा को एक फीसदी वोट नहीं मिला था, जबकि टीटीपी ने 39 फीसदी वोट हासिल किए थे। फिर भी टीटीपी और जन सेना पार्टी के साथ तालमेल में भाजपा छह सीटें लड़ेगी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तो भाजपा का समझौता चुनाव में शिव सेना के साथ तालमेल में भाजपा 25 सीटों पर लड़ी थी लेकिन इस बार दो सहयोगी होने के बावजूद वह 30 सीटों पर लड़े की तैयारी कर रही है। असली शिव सेना और असली एनसीपी के लिए वह सिर्फ 18 सीटें छोड़ा चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपना दल के अलावा राष्ट्रीय लोकदल और सुहृलदेव भारतीय समाज पार्टी को भी अपने गठबंधन में शामिल किया है लेकिन अपनी शर्तों पर। यजंत चौधरी की पार्टी गलोद को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की सात सीटें दी थीं लेकिन वे भाजपा के साथ सिर्फ दो सीटों पर लड़े को तैयार हो गए। चार पार्टियों के साथ तालमेल के बावजूद उत्तर प्रदेश में भाजपा 74 सीटों पर लड़े वाली है ऐसा नहीं है कि भाजपा ने सिर्फ सीटों के बंटवारे में अपनी मर्जी चलाई है।

नागरकृता
सिविल एबे

आखरिकार दश म लागू हा गया है। इस कानून को लागू करना क्या मोर्चा सरकार की मजबूरी थी। यह कानून क्या इतना आवश्यक था कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लागू किया जाता क्या यह कानून पूरी तरह से पारदर्शी और देश के हित में है। क्या भारीतास मुसलमानों की नागरिकता पर इस कानून का कोई असर पड़नेवाला है। अगर ऐसा नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े क्यों क

इस कानून पर भ्रम क्यों फैला रहा है। क्या चुनावी लाभ के लिए विषयक मुसलमानों में असुरक्षा की भावना पैदा करना चाहता है। क्या मुस्लिम वोटों के ध्वनीकरण के लिए इस कानून के संबंध में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है? सवाल उठता है की क्या मोदी सरकार वास्तव में पारदर्शी रूप से इस कानून को लागू किया है। क्या सरकार कानून के जरिए, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और इसाई समुदाय का ध्वनीकरण करना चाहती है। लोकसभा चुनाव के

वह कानून एटा भूस्तम ह। कानून के लागू होने के बाद ४८ रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या देश के किसी नागरिक की नागरिकता समाप्त के लिए वह कानून लाया गया सब भ्रामक प्रचार है। इस कानून तरह का कोई प्रावधान नहीं है में रहने वाले गैर हिंदू यानी मुसलमानों की नागरिकता पर कोई सवाल उठाता है। यह कानून सिर्फ उसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों नागरिकता प्रदान करेगा जो पाकिस्तान, ब

इस भारत में विक्री करने करता है। यह इस भारतीय नागरिकता प्रदान करती रहेगी। वैसे यह साबित करना भी एक मुश्किल काम होगा कि सम्बंधित देशों से भारत आए लोगों में कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहु संख्यक। क्या इस कानून के लागू होने के बाद पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से अवैध रूप से आए मुस्लिम भारत में आ जाएंगे? यह भारत के लिए समय तक धरना प्रदर्शन भी चला गया है। लोगों को अपनी जान रंग वानी पड़ी है। दलिलों के शाहीनबाग में लंबे समय तक धरना प्रदर्शन भी चला गया है। साल 2019 के पहले भारतीय नागरिकता लिए वे लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था लेकिन बाद में इसे घटाकर 6 साल कर दिया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों मुस्लिम देशों के बहुल देश हैं। वहाँ मुस्लिम नहीं

संक्षिप्त समाचार
इयूटीपर तैनात आईपीएस
ऑफिसर को मंत्री के
काफिले ने मारी टक्कर



हैदराबाद। तेलंगाना सरकार में मंत्री श्रीधर बाबू के काफिले ने अईपीएस अधिकारी परिवार पंकज को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि वह मामूली रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, भद्राद्वी पीठागुडेम जिले के एसपी परिवार पंकज उस समय घायल हो गए, जब मंत्री के काफिले में सवार एक वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। वाहन के बक्क वह ड्यूटी पर थे। इसी दौरान पीछे से आ रही गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। गाड़ी से टक्करते ही वह जमीन पर गिर गए। हालांकि, मीके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें उचाया और इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। बता दें कि भद्राद्वी पीठागुडेम जिले के एसपी परिवार पंकज उनके कार्यक्रम को लेकर ड्यूटी पर ही तैनात थे, जब यह हादसा हुआ।

**पहले कश्मीरी पंडितों को
वापस लाओ फिर सीएए
लागू करना- उद्धव ठाकरे**

मुंबई, एजेंसी। नारायिका संसोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होते ही सियासत तेज हो गई। सत्ता पक्ष जहां इसका स्वागत कर रहा है, वहां सेवा विषयक इसकी आलाचना कर रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इसकी आलोचना की और सरकार की मंसार पर सवाल उठाया है। उन्होंने मंगलवार को कहा, देश में नया कानून सीएए लाया गया है। जो दिन, सिख, पारसी और जैन देश के बाहर देर हुए हैं, उन्होंने हमारे देश में लाया जाएगा। उन्हें जरूर लाया जाए, लेकिन यह सिर्फ एक चानवी ढक्कांडा है। ठाकरे ने आगे कहा, जब मैं सीएए था, तो भाजपा देश में सीएए और एनआरसी का भूत लेकर आई थी। उस समय लोगों के मन में दूर पैदा हो गया, खासकर असपाई के लोगों के मन में। इस कानून के खिलाफ कोर्ट में कई आधिकारियों हैं। अपने कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन उन्होंने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शिवसेना (युवांटी) सुप्रीमो ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर धर्म के नाम पर भेदभाव पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, धर्मों के बीच भेदभाव पैदा कर राज्य और दूसरी दौरान लाया जाता है। उन्होंने जरूरी राज्य करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, धर्मों के बीच नकार पैदा कर रही है और दूसरी तरफ देशभक्त इंडिया गठबंधन है। यह चुनाव देशभक्त बनाम नफरत करने वालों के बीच होते जा रहे हैं। अगर आप विदेशों से हिंदुओं को हमारे यहां लाना चाहते हैं तो पहले कश्मीरी पंडितों को वापस लाओ और फिर सीएए लाओ।

**चुनाव आयोग से जम्मू-कश्मीर में
लोकसभा चुनाव के साथ-साथ
विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह**

जम्मू, एजेंसी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों जम्मू-कश्मीर के तीन विधायिका दौरे पर है। केंद्र शासित प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों ने समीक्षा के लिए आयोग के अधिकारियों ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के साथ योग्यता प्रमाण शुरू किया। इस दौरान भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने आयोग से जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह किया। भाजपा ने भी लोकसभा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने पर सहमति जताई है। भरतीय जनता पार्टी (भाजपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पार्टी नेता और पूर्व मंत्री नासिर असलम वाहनी ने कहा कि उन्होंने विधान आयोगों को लोकसभा चुनावों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की भी मांग की है।

**चीन के हेबैई में एक रेस्टरां में धमाका,
एक की मौत; 22 से अधिक घायल**

बीजिंग, एजेंसी। चीन के हेबैई प्रांत के सान हे शहर में बुधवार को एक रेस्टरां में हुए जरबदस्त धमाकों के माम से कम एक व्यक्ति जान लेता है, वहीं 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया गया है कि धमाका इतने तेज था कि आसपास की कई कारों और इमारतों का भारी नुकसान पहुंचा है।

चीनी मौडियो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह घटना स्थानीय समयानुसार सुबह 8 बजे बीजिंग से करोब 80 किमी दूर साहे शहर में हुई। घटनालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, विस्फोट एक गैस सिलेंडर के लैंपेज के बाद हुआ। चीन के गहर-बचाव विभाग ने कहा कि लोगों को सुशिक्षण किया जाना चाहिए कि लोगों के लैंपेज के बाद हुआ। चीन के गहर-बचाव विभाग ने कहा कि लोगों को घायल होने के लिए 36 वाहन और 154

बचावकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके बाद आग को काब में कर लिया गया। गैरतलव है कि बीजिंग में कुछ उच्चस्तरीय बैठकों के तीक बाद ही इस धमाके की खबर आई है। सोशल मीडिया

पर जो बीडियो वायरल हुए हैं, उनमें धमाके के बाद रेस्टरां से धुआं उठता देखा जा सकता है। इसके अलावा कई गाड़ियों के टूटे शीशे और आसपास इमारों का मलबा भी गिरा है।

कीव, एजेंसी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। तीसरे साल में प्रवेश कर चुका यह महायुद्ध लाखों कल्पेआम और अरबों के नुकसान के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। इस युद्ध में नाटो और अमेरिका के दम पर यूक्रेन से पुतिन की खतरनाक आर्मी को लौही के चने

चबवा रही है। पुतिन लगातार यूक्रेन से युद्ध में धमाकों की दखल अदांदा जो पर अपने तेवर दिखा चुके हैं। पुतिन ने हल ही में नाटो देश के यूक्रेन में अपनी आर्मी भेजने के बाद कड़ा ऐरोपांतर जाता था। पुतिन ने बाकायदा परमाण बम से हमले की धमकी दी थी। पुतिन की धमकी का असर यह हुआ कि इसने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की घोषणा वापस ले ली

है।

यहां नाटो देश पोलैंड की बात हो रही है।

नाटो मंबर पोलैंड ने यूक्रेन में सेना भेजने के लिए फैसला लिया है। एक नए बायन में पोलैंड ने कहा है कि यूक्रेन में सेना भेजने के लिए हमारी कोई योजना नहीं है। मामले की जानकारी खबरे वाले लोगों का मानन है कि पोलैंड के बायन भी इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इसके बाद हमें एकाधार योग्य आदेश दिया गया। इससे भी मानन है कि आदेश दिया गया।

पोलैंड ने कहा है कि यूक्रेनी सेवा सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए भी सेना नहीं भेजी जाएगी। यह बायन हुए है कि बायन राष्ट्रपति व्लादिमीर चुर्किन ने परिचय द्वारा यूक्रेन में सेना भेजने पर परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है।

परिचय के द्वायल से गुस्साए

पूर्ण

प्रतिवेदन के बायन में भी जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कदम का कारण आदेश दिया गया।